



*The*  
**ACHIEVERS**  
IAS ACADEMY  
PATNA

*Daily*  
**NEWS CHRONICLE**

**IDEAL FOR**

For UPSC/BPSC & For other Exams

**Hindi**

**NEWS CREDIT**

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

**NEWS COVERED**

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



**Tuesday, August 18, 2026**



+91 8434931877



[www.achieversiaspatna.co.in](http://www.achieversiaspatna.co.in)



[achieversiaspatna@gmail.com](mailto:achieversiaspatna@gmail.com)

## दिन की प्रमुख घटनाएं

- भारत 18 अगस्त को नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा
- राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 15 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित करेगा
- सीबीडीटी ने छोटे करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक विदेशी संपत्ति के प्रकटीकरण के लिए फास्ट-डीएस 2026 लॉन्च किया
- मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरे साल ईसपोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब जीता
- RBI ने 2027 से उधारकर्ता सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए ऋण वसूली नियम पेश किए
- सेबी ने ऋण सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन को सरल बनाने के लिए ऋण जोखिम-ओ-मीटर का प्रस्ताव रखा
- कीर्ति चक्र विजेता मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान का 71 वर्ष की आयु में निधन
- शांति नियम 2026 का मसौदा ऑपरेटरों के लिए परमाणु दायित्व और बीमा ढांचे का प्रस्ताव करता है
- हिमाचल प्रदेश ने पेट्रोल-डीजल पर विधवा और अनाथ उपकर लगाया
- सरकार दीर्घकालिक बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति का गठन करेगी
- इस्लाम मखचेव ने UFC 330 में सत्रहवीं सीधी जीत के साथ UFC रिकॉर्ड बनाया

## भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा



### यह खबरों में क्यों है?

- भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

### मुख्य बिंदु

- बैठक: 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक
- स्थान: नई दिल्ली, भारत
- मेजबान देश: भारत
- ब्रिक्स अध्यक्षता: भारत, 2026
- अध्यक्ष: भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
- भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय: "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण"

### बैठक का उद्देश्य क्या है?

### यह बैठक ब्रिक्स देशों को निम्नलिखित के लिए एक मंच प्रदान करेगी:

- प्रमुख पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करें।
- पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग को मजबूत करना।
- विचारों, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करें।
- सतत विकास और जलवायु कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाएं।
- पर्यावरण के मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना।

### भारत की चार प्रमुख पर्यावरणीय प्राथमिकताएं

- अपनी 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के माध्यम से सहयोग के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:
- सतत जीवन शैली: पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देना और लोगों को प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- वनीकरण, वन अग्नि प्रबंधन और आपदा लचीलापन: ब्रिक्स देश वन क्षेत्र बढ़ाने, जंगल की आग के प्रबंधन और पर्यावरणीय आपदाओं के खिलाफ तैयारियों में सुधार करने पर सहयोग करेंगे।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था: नए कच्चे माल पर अपशिष्ट और निर्भरता को कम करते हुए संसाधनों के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।
- अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से कमजोर समुदायों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए देशों की क्षमता को मजबूत करना।

### मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले की बैठकें

- मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा होगी।

### इसमें शामिल हैं:

- ब्रिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
- पर्यावरण कार्य समूह
- जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर संपर्क समूह
- ये बैठकें मंत्री स्तर पर चर्चा और निर्णयों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती हैं।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- ब्रिक्स मूल रूप से: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, समूह का विस्तार ब्रिक्स से ब्रिक्स तक किया।
- वर्तमान सदस्यता: ब्रिक्स का काफी विस्तार हुआ है और अब इसमें 11 पूर्ण सदस्य शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब।
- भारत की भूमिका: भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसने 2012 और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों की मेजबानी की है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी): 2015 में ब्रिक्स द्वारा स्थापित, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। यह सदस्य और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

## राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026: डॉ. जितेंद्र सिंह 15 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे



यह खबरों में क्यों है?

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) 17 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9वां राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 13 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 15 चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे।

मुख्य बिंदु

| विशेष                    | विवरण                                |
|--------------------------|--------------------------------------|
| धनराशि देना              | राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026        |
| संस्करण                  | 9वां राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार समारोह |
| द्वारा सम्मानित किया गया | डॉ. जितेंद्र सिंह                    |

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| मंत्रालय          | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय           |
| कार्यान्वयन विभाग | पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) |
| पुरस्कार विजेता   | 15 सेवानिवृत्त कर्मचारी                          |

अनुभव प्लेटफॉर्म क्या है?

- प्रधानमंत्री की पहल पर मार्च 2015 में अनुभव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, ताकि सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा के वर्षों से अपने अनुभवों, उपलब्धियों और सुझावों को दस्तावेज करने और साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।

इसमें निम्नलिखित के कर्मचारी शामिल हैं:

- केंद्र सरकार
- 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026

2026 योजना के तहत:

- 5 सर्वश्रेष्ठ लेखों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 10 अन्य उत्कृष्ट लेखों को जूरी प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।
- इस प्रकार, कुल 15 मान्यताएं दी गई हैं।

## छोटे करदाताओं के लिए सीबीडीटी की फास्ट-डीएस 2026 योजना लागू हुई



यह खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने छोटे करदाताओं की विदेशी परिसंपत्ति-प्रकटीकरण योजना (FAST-DS), 2026 को अधिसूचित किया है। वन-टाइम स्कीम 16 अगस्त 2026 को लागू हुई और पात्र करदाताओं को स्वेच्छा से कुछ पहले से अघोषित विदेशी संपत्ति या विदेशी आय का खुलासा करने की

अनुमति देगी। घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। इस तिथि के बाद कोई घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

फास्ट-डीएस 2026 क्या है?

- फास्ट-डीएस का मतलब छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति - प्रकटीकरण योजना है।
- यह वित्त अधिनियम, 2026 के अध्याय IV के तहत शुरू की गई एक बार की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना है। यह विशेष रूप से छोटे करदाताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अनजाने में अपने आयकर रिटर्न में कुछ विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा करने में विफल रहे हैं।

कौन लाभ उठा सकता है?

यह योजना करदाताओं के लिए उपयोगी हो सकती है जैसे:

- छात्र या युवा पेशेवर जिनके पास विदेशी बैंक खाते या निवेश हैं।
- विदेशी ईएसओपी, आरएसयू या इसी तरह की प्रतिभूतियां प्राप्त करने वाले कर्मचारी।
- जो लोग विदेश में काम करते थे और भारत लौट आए थे।
- विदेशी संपत्ति या बचत के साथ पूर्व एनआरआई।
- ऐसे करदाता जिन्होंने पहले ही आय पर कर का भुगतान कर दिया था, लेकिन अपने आईटीआर में संबंधित विदेशी संपत्ति की रिपोर्ट करने में विफल रहे।

### क्या खुलासा किया जा सकता है?

- इस योजना में मोटे तौर पर दो श्रेणियां शामिल हैं:
- अघोषित विदेशी संपत्ति या आय
- करदाता कुछ विदेशी संपत्ति या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था या कर लगाने की पेशकश नहीं की गई थी, बशर्ते कुल मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक न हो।

### करदाता को आम तौर पर भुगतान करना होगा:

- 30% कर, प्लस
- अतिरिक्त 30% लेवी
- यह प्रभावी रूप से योजना के तहत लागू मूल्य का 60% है।

### आईटीआर में विदेशी संपत्ति की सूचना नहीं दी गई

### इस श्रेणी में विदेशी संपत्ति शामिल है जो:

- उस आय से प्राप्त किया गया था जिस पर पहले से ही कर लगाया जा चुका था, या
- जब करदाता अनिवासी था तब अधिग्रहित किया गया था, लेकिन
- आईटीआर की संबंधित विदेशी-संपत्ति अनुसूची में रिपोर्ट नहीं किया गया था।
- ऐसी एसेट के लिए, लागू सीमा ₹5 करोड़ है, जिसमें ₹1 लाख शुल्क है।

### महत्वपूर्ण तिथियां और सीमाएं

| विशेष                                                    | विवरण                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| षड्यंत्र रचना                                            | फास्ट-डीएस 2026                                 |
| फुल फॉर्म                                                | छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति-प्रकटीकरण योजना |
| से प्रभावी                                               | 16 अगस्त 2026                                   |
| अंतिम तिथि                                               | 31 दिसंबर 2026                                  |
| अघोषित विदेशी संपत्ति/आय सीमा                            | ₹1 करोड़ तक                                     |
| पहले कर लगाया गया लेकिन गैर-रिपोर्ट की गई विदेशी संपत्ति | ₹5 करोड़ तक                                     |
| दूसरी श्रेणी के लिए शुल्क                                | ₹1 लाख                                          |
| प्रकृति                                                  | एक बार का स्वेच्छिक प्रकटीकरण                   |

### मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरे साल ईस्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब जीता



### यह खबरों में क्यों है?

- नॉर्वे के विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरे वर्ष ईस्पोर्ट्स विश्व कप (EWC) शतरंज का खिताब जीता है। टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व करते हुए, कार्लसन ने पेरिस, फ्रांस में फाइनल में बेलारूसी ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया।

### अन्य पदक पद

- संयुक्त राज्य अमेरिका के हिकारू नाकामुरा तीसरे स्थान की प्रतियोगिता में अलरीजा फिरौजा को हराकर तीसरे स्थान पर रहे। नाकामुरा ने \$145,000 का

पुरस्कार भी हासिल किया। कार्लसन ने 250,000 डॉलर कमाए, जबकि उपविजेता लाजाविक ने 190,000 डॉलर कमाए।

### ईस्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज इवेंट के बारे में

- शतरंज प्रतियोगिता पेरिस में आयोजित बड़े ईस्पोर्ट्स विश्व कप 2026 का हिस्सा थी। शतरंज ने 2025 संस्करण में पेश किए जाने के बाद ईस्पोर्ट्स विश्व कप में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज की।
- शतरंज प्रतियोगिता में बिना वेतन वृद्धि के 10 मिनट का तेजी से समय नियंत्रण दिखाया गया, जिसमें खिलाड़ी क्वालीफाईंग, समूह और नॉकआउट चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहे थे।
- कार्लसन ने फाइनल में अलरीजा फिरौजा को हराकर उद्घाटन 2025 ईस्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज खिताब भी जीता था। इसलिए उनकी 2026 की जीत ने उन्हें दो बार EWC शतरंज का खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना दिया।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

- विजेता: मैग्नस कार्लसन
- राष्ट्रीयता: नॉर्वेजियन

- खेल: शतरंज
- टूर्नामेंट: ईसपोर्ट्स विश्व कप 2026
- स्थान: पेरिस, फ्रांस
- उपविजेता: डेनिस लाज़ाविक - बेलारूस

- तीसरा स्थान: हिकारू नाकामुरा - यूएसए
- विजेता टीम: टीम लिक्विड
- विजेता का पुरस्कार: यूएस \$ 250,000

### RBI ने नए ऋण वसूली नियम पेश किए: 2027 से उधारकर्ताओं के लिए मजबूत सुरक्षा



यह खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण वसूली प्रथाओं को विनियमित करने और उधारकर्ताओं को उत्पीड़न, गोपनीयता उल्लंघन और अनुचित वसूली विधियों से बचाने के लिए नए नियम पेश किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट

मुख्य बिंदु

- रिकवरी कॉल: एजेंट आम तौर पर उधारकर्ताओं से केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं।
- भौतिक दौरे: पहली पुनर्प्राप्ति यात्रा से पहले कम से कम एक दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है।
- कोई उत्पीड़न नहीं: धमकी, अपमानजनक भाषा, सार्वजनिक अपमान और उधारकर्ताओं को शर्मिंदा करने के लिए रिश्तेदारों या सहकर्मियों से संपर्क करना प्रतिबंधित है।
- ऋणदाता की जिम्मेदारी: बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं अपने वसूली एजेंटों के आचरण के लिए जिम्मेदार रहती हैं।

- कॉल रिकॉर्ड: पुनर्प्राप्ति से संबंधित संचार रिकॉर्ड को छह महीने तक संरक्षित किया जाना चाहिए।
- डिवाइस लॉकिंग: वित्तपोषित उपकरणों की रिमोट लॉकिंग सुरक्षा उपायों के अधीन होगी और मनमाने ढंग से उपयोग नहीं की जा सकती है।
- डेटा सुरक्षा: पुनर्प्राप्ति तकनीक संवेदनशील जानकारी जैसे संपर्क, संदेश, फ़ोटो या कॉल लॉग तक नहीं पहुँच सकती है।
- मुआवजा: गलत उपकरण प्रतिबंध पर प्रति घंटे ₹250 का मुआवजा लग सकता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- नए ढाँचे का उद्देश्य ऋणदाताओं के ऋण वसूली के अधिकार को उधारकर्ताओं के निजता, गरिमा और उचित व्यवहार के अधिकारों के साथ संतुलित करना है। यह ऋणदाताओं को तृतीय-पक्ष रिकवरी एजेंसियों के लिए अधिक जवाबदेह बनाता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- से प्रभावी: 1 जनवरी 2027
- पुनर्प्राप्ति संपर्क घंटे: सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक
- पहली यात्रा के लिए अग्रिम सूचना: 1 दिन
- कॉल-रिकॉर्ड संरक्षण: 6 महीने
- डिवाइस प्रतिबंध मुआवजा: ₹250/घंटा
- मुख्य उद्देश्य: उत्पीड़न को रोकना और उचित ऋण वसूली प्रथाओं को सुनिश्चित करना

### सेबी ने निवेशकों को जोखिम का आकलन करने में मदद करने के लिए ऋण प्रतिभूतियों के लिए ऋण जोखिम-ओ-मीटर का प्रस्ताव रखा



यह खबरों में क्यों है?

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए एक कलर-कोडेड क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के लिए बांड और अन्य ऋण साधनों के क्रेडिट/डिफॉल्ट जोखिम को समझना आसान बनाना है।

### क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर क्या है?

- यह एक दृश्य जोखिम संकेतक होगा, जो म्यूचुअल फंड के लिए उपयोग किए जाने वाले रिस्क-ओ-मीटर के समान होगा।
- प्रस्ताव के तहत, ए से डी तक की मौजूदा क्रेडिट रेटिंग को छह रंग-कोडित जोखिम श्रेणियों में मैप किया जाएगा। यह निवेशकों को जटिल रेटिंग प्रतीकों की व्याख्या किए बिना सापेक्ष क्रेडिट जोखिम को समझने की अनुमति देगा।
- सेबी का प्रस्तावित मीटर इन रेटिंगों को छह आसानी से समझ में आने वाले दृश्य जोखिम स्तरों में परिवर्तित करता है, जिससे निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों की अधिक आसानी से तुलना करने और उनकी जोखिम उठाने की क्षमता के साथ उनका मिलान करने की अनुमति मिलती है।

### यह कैसे काम करेगा?

| क्रेडिट रेटिंग       | प्रस्तावित जोखिम स्तर              | सरल अर्थ                    |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ए                    | सबसे कम क्रेडिट जोखिम              | डिफॉल्ट की बहुत कम संभावना  |
| एए+, एए, एए-         | बहुत कम क्रेडिट जोखिम              | मजबूत पुनर्भुगतान क्षमता    |
| ए+, ए, ए-            | कम क्रेडिट जोखिम                   | अपेक्षाकृत कम क्रेडिट जोखिम |
| बी+, बीबीबी, बीबीबी- | मध्यम ऋण जोखिम                     | ऋण जोखिम का मध्यम स्तर      |
| बीबी +, बीबी, बीबी-  | डिफॉल्ट का मध्यम जोखिम             | डिफॉल्ट की उच्च संभावना     |
| बी + से डी           | डिफॉल्ट का उच्च से बहुत अधिक जोखिम | चुकोती विफलता का उच्च जोखिम |

- प्रत्येक श्रेणी का एक अलग रंग होगा, जो सुरक्षित से लेकर जोखिम भरे स्तर तक होगा।
- क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर को प्रस्ताव दस्तावेजों, संक्षिप्त विवरणिकाओं, निजी प्लेसमेंट ज्ञापनों और विज्ञापनों में प्रदर्शित किया जाएगा।

### यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य कॉरपोरेट बॉन्ड/ऋण बाजार को अधिक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाना है। खुदरा निवेशकों को केवल तकनीकी क्रेडिट-रेटिंग प्रतीकों पर भरोसा करने के बजाय डिफॉल्ट की संभावना के आधार पर बॉन्ड की तुलना करना आसान हो सकता है।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

- सेबी: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- प्रस्ताव: क्रेडिट जोखिम-ओ-मीटर
- इन पर लागू: ऋण प्रतिभूतियां
- जोखिम श्रेणियां: 6
- क्रेडिट-रेटिंग रेंज: ए से डी
- मॉडल: Mutual Fund Risk-o-Meter के समान
- OBPP: ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता
- मुख्य उद्देश्य: ऋण/डिफॉल्ट जोखिम का आसान मूल्यांकन और तुलना

### कीर्ति चक्र विजेता मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान का 71 वर्ष की आयु में निधन



### यह खबरों में क्यों है?

- कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता और भारतीय सेना के पहले व्हीलचेयर पर सवार जनरल मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान (सेवानिवृत्त) का 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे।

### मेजर जनरल सुनील राजदान कौन थे?

- मेजर जनरल राजदान 7 वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) से संबंधित थे। वह 1994 में जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने असाधारण साहस के लिए जाने जाने लगे।
- 1994 में, तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल राजदान ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाई गई युवतियों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया था।
- ऑपरेशन के दौरान, उसने दो आतंकवादियों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित बचाने में मदद की।
- उन्हें कई बंदूक की गोली के घाव हुए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें कमर के नीचे लकवा मार गया।
- अपनी विकलांगता के बावजूद, उन्होंने अपना सैन्य करियर जारी रखा और मेजर जनरल बनने के लिए रैंकों के माध्यम से आगे बढ़े।
- उनकी उपलब्धि ने उन्हें भारतीय सेना का पहला व्हीलचेयर पर चलने वाला जनरल बना दिया।

### कीर्ति चक्र

- 1994 के आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए, राजदान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था।
- कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो असाधारण बहादुरी और युद्ध के मैदान से दूर बलिदान के लिए दिया जाता है।
- वह विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम) के प्राप्तकर्ता भी थे।

### उनकी कहानी क्यों महत्वपूर्ण है?

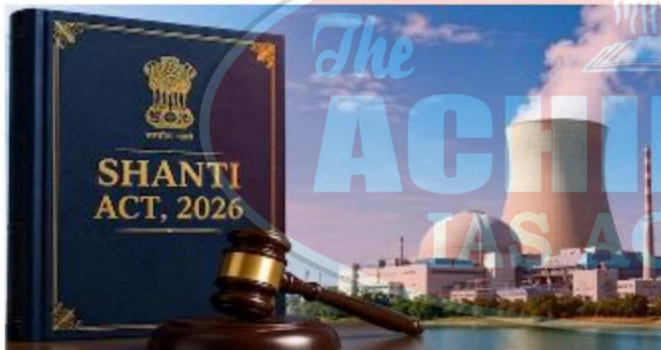
- मेजर जनरल राजदान का करियर न केवल उनकी युद्ध के मैदान की बहादुरी के लिए उल्लेखनीय है, बल्कि जीवन बदलने वाली चोट से पीड़ित होने के बाद देश की सेवा जारी रखने के उनके दृढ़ संकल्प के लिए भी उल्लेखनीय है।

- व्हीलचेयर पर रहने के बावजूद मेजर जनरल के पद तक उनकी वृद्धि को साहस, लचीलापन और सैन्य सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

- नाम: मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान (सेवानिवृत्त)
- रेजिमेंट: 7 वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल)
- वीरता पुरस्कार: कीर्ति चक्र
- कीर्ति चक्र: भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार
- ऑपरेशन: जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, 1994
- ऐतिहासिक उपलब्धि: भारतीय सेना के पहले व्हीलचेयर पर सवार जनरल
- अन्य पुरस्कार: विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम)

## शांति नियम 2026: सरकार ने ऑपरेटरों के लिए परमाणु दायित्व और बीमा ढांचे का प्रस्ताव रखा



### चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से 14 अगस्त, 2026 को शांति नियम, 2026 का मसौदा जारी किया, जिसमें परमाणु संयंत्र संचालकों के लिए नागरिक दायित्व, बीमा और वित्तीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।

### प्रमुख प्रावधान

- सख्त 'नो-फॉल्ट' देयता
- परमाणु प्रतिष्ठानों के संचालक किसी भी परमाणु क्षति के लिए बिना किसी गलती के आधार पर सख्ती से उत्तरदायी होंगे।
- यह दायित्व परमाणु सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को भी कवर करेगा।

### अनिवार्य बीमा और वित्तीय सुरक्षा

- नियम 77 के तहत, ऑपरेटरों को बीमा पॉलिसी, वित्तीय सुरक्षा या दोनों का संयोजन बनाए रखना होगा।

- वित्तीय सुरक्षा तब तक वैध रहनी चाहिए जब तक कि रिएक्टर कोर से निकाले गए सभी खर्च किए गए ईंधन को भंडारण पूल से बाहर नहीं निकाल लिया जाता है।
- यदि शेयर, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें केंद्र सरकार के साथ गिरवी रखा जाना चाहिए और 1:1.33 सुरक्षा मार्जिन बनाए रखना चाहिए।

### देयता कैप समीक्षा

- केन्द्र सरकार नाभिकीय क्षति के लिए प्रचालक के असैन्य दायित्व की अधिकतम सीमा की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार एक विशेषज्ञ समूह का गठन करेगी।
- इस समूह में परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग, बीमा, कानून और जनहित के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

### सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान

- कुछ मामलों में, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले परमाणु प्रतिष्ठानों के ऑपरेटरों को बीमा या वित्तीय सुरक्षा लेने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
- इसके बजाय, केंद्र सरकार उस नुकसान के लिए जिम्मेदारी लेगी जिसके लिए ऑपरेटर जिम्मेदार है।

### देयता सीमा (शांति अधिनियम के तहत)

- शांति अधिनियम के तहत, परमाणु प्रतिष्ठान की श्रेणी के आधार पर प्रति परमाणु घटना पर अधिकतम ऑपरेटर देयता ₹1,000 करोड़ (\$ 10.4 मिलियन) से ₹ 30,000 करोड़ तक होगी।

### महत्वपूर्ण तिथियां और आंकड़े

| विशेष                   | विवरण                         |
|-------------------------|-------------------------------|
| मसौदा नियम जारी         | अगस्त 14, 2026                |
| मंत्रालय                | अणु ऊर्जा विभाग               |
| ढोंग                    | शांति अधिनियम, 2025           |
| देयता कैप               | ₹1,000 करोड़ से ₹30,000 करोड़ |
| समीक्षा अवधि            | हर 5 साल में                  |
| वित्तीय सुरक्षा मार्जिन | 1:1.33                        |

### यह क्यों मायने रखता है

- यह ढांचा भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु प्रतिष्ठानों के पूरे जीवनचक्र के

लिए वित्तीय व्यवस्था की जाए - संचालन, अपशिष्ट प्रबंधन, डीकमीशनिंग और साइट उपचार।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

- शांति: भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नति
- अधिनियम: शांति अधिनियम, 2025
- मंत्रालय/विभाग: परमाणु ऊर्जा विभाग
- मुख्य प्रावधान: परमाणु क्षति के लिए बीमा/वित्तीय सुरक्षा
- देयता: श्रेणीबद्ध देयता ढांचा
- क्षेत्र: परमाणु ऊर्जा
- प्रमुख उद्देश्य: परमाणु क्षति के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए परमाणु विस्तार और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- भारत का दीर्घकालिक परमाणु लक्ष्य: 2047 तक 100 गीगावॉट

## उपकर की व्याख्या: सरकारें कल्याण और विकास के लिए उद्देश्य-विशिष्ट लेवी का उपयोग कैसे करती हैं



### यह खबरों में क्यों है?

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर लगाया है। राजस्व का उपयोग विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण उपायों के लिए किया जाएगा। यह लेवी 11 अगस्त 2026 से लागू हुई।

### उपकर क्या है?

- उपकर एक विशिष्ट, निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर है। सामान्य कर राजस्व के विपरीत, जो आम तौर पर सरकार के समग्र राजस्व पूल में जाता है, उपकर राजस्व स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क या श्रमिक कल्याण जैसे विशेष उद्देश्य के लिए होता है। इसे कभी-कभी "कर पर कर" कहा जाता है, खासकर जब यह मौजूदा कर देयता पर लगाया जाता है। हालांकि, हर उपकर इस तरह से काम नहीं करता है; कुछ सीधे ईंधन, निर्माण लागत या विशिष्ट लेनदेन पर लगाए जाते हैं।

### उपकर बनाम कर

| प्रवर्तन-बिंदु | टैक्स                                 | उपकर                                        |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| उद्देश्य       | सामान्य सरकारी व्यय                   | विशिष्ट उद्देश्य                            |
| उपयोग          | सरकारी गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला | नामित गतिविधि/कार्यक्रम                     |
| उदाहरण         | इनकम टैक्स, जीएसटी                    | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, बीओसीडब्ल्यू उपकर |
| प्रकृति        | सामान्य राजस्व                        | उद्देश्य-विशिष्ट राजस्व                     |

### महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु

- संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत, केंद्रीय उपकर और अधिभार राजस्व को करों के विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है। इसलिए, इन राजस्वों को सामान्य कर-हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।

### कल्याण/विकास उपकरों के उदाहरण

- बीओसीडब्ल्यू उपकर: निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि लागत को छोड़कर निर्माण लागत पर 1% उपकर।
- केरल: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन के लिए पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाया गया है।
- जम्मू और कश्मीर: पेट्रोल और डीजल पर रोजगार उपकर।

- लद्दाख: पेट्रोल-डीजल पर रोजगार उपकर।
- मिजोरम: पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेस
- नागालैंड: पेट्रोलियम उत्पादों पर ₹2 प्रति लीटर सड़क रखरखाव उपकर।
- त्रिपुरा: पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस पर सड़क विकास उपकर।

#### यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- उपकर सरकारों को विशिष्ट कल्याण या विकास कार्यक्रमों के लिए धन का एक समर्पित स्रोत बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि, संघ स्तर पर, विभाज्य पूल से उनके बाहर होने का मतलब है कि उच्च उपकर संग्रह राज्यों के साथ साझा करने के लिए उपलब्ध कर राजस्व की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।

#### परीक्षा फोकस पॉइंट

- उपकर: किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 270
- संघ उपकर: विभाज्य पूल से बाहर रखा गया
- हिमाचल प्रदेश: पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर विधवा और अनाथ उपकर
- बीओसीडब्ल्यू उपकर: निर्माण लागत का 1%, भूमि को छोड़कर
- BOCW: भवन और अन्य निर्माण श्रमिक
- केरल: ₹2/लीटर सामाजिक सुरक्षा उपकर
- नागालैंड: ₹2/लीटर सड़क रखरखाव उपकर
- त्रिपुरा: सड़क विकास उपकर

### सरकार दीर्घकालिक बैंकिंग सुधारों के लिए उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति का गठन करेगी



#### यह खबरों में क्यों है?

- केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के लिए तैयार है। समिति भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करेगी और 2047 की ओर देश के दीर्घकालिक विकास के लिए इसे तैयार करने के लिए सुधारों का सुझाव देगी।

#### समिति क्या जांच करेगी?

- बैंकिंग क्षेत्र का समेकन, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का भविष्य।
- बैंकों की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए शासन सुधार।
- डिजिटल परिवर्तन और नई तकनीकों को अपनाना।
- वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।
- भारत के आर्थिक विस्तार का समर्थन करने के लिए ऋण और जमा वृद्धि।
- भारतीय बैंकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता।
- वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को बनाए रखते हुए बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के उपाय।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ध्यान

- हालांकि समिति के जनादेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों बैंकों को शामिल करने की उम्मीद है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर अधिक ध्यान दिए जाने की संभावना है।
- संभावित मुद्दों में छोटे बैंकों का समेकन और उनके पैमाने, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना शामिल है। हालांकि, विशिष्ट विलय प्रस्तावों और समिति की अंतिम सिफारिशों की अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है।

#### एमएसएमई के लिए समर्थन

- विचाराधीन एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच में सुधार करना है। समिति व्यापार प्राप्ति के लिए बाजार को सुरक्षित और व्यापक बनाने के तरीकों की जांच कर सकती है, जिसमें TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) के माध्यम से उत्पन्न प्राप्ति शामिल हैं। इससे छोटे व्यवसायों को अधिक आसानी से धन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और केवल बैंक ऋण पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है।

#### यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ भारत के बैंकिंग क्षेत्र को काफी अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसलिए समिति से सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप एक मजबूत, अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग प्रणाली के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने की उम्मीद है।

### परीक्षा फोकस पॉइंट

- समिति: विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति
- में घोषित: केंद्रीय बजट 2026-27
- वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
- नोडल विभाग: वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय
- मुख्य उद्देश्य: बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा और दीर्घकालिक सुधार

- विजन: बैंकिंग क्षेत्र को विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ा गया
- प्रमुख क्षेत्र: समेकन, शासन, डिजिटलीकरण, वित्तीय समावेशन और ऋण वृद्धि
- फोकस: निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अधिक ध्यान देने की उम्मीद है
- एमएसएमई फोकस: प्राप्ति के वित्तपोषण और टीआरईडीएस के माध्यम से ऋण तक पहुंच में सुधार

**इस्लाम मखचेव ने 17वीं सीधी जीत के साथ UFC रिकॉर्ड बनाया, UFC 330 में इयान मचाडो गैरी को हराया**



- रूसी एमएमए फाइटर इस्लाम मखचेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में UFC 330 में सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से आयरलैंड के इयान मचाडो गैरी को हराकर अपनी UFC वेल्टरवेट चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत ने मखचेव को लगातार 17 जीत दिलाई, जो एंडरसन सिल्वा के 16 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।

### मुख्य बिंदु

- घटना: UFC 330
- स्थल: फिलाडेल्फिया, पेन्सिल्वेनिया, यूएसए
- विजेता: इस्लाम मखचेव
- राष्ट्रियता: रूस
- प्रतिद्वंद्वी: Ian Machado Garry
- शीर्षक: UFC वेल्टरवेट चैंपियनशिप
- जीत का सिलसिला : लगातार 17 UFC जीत
- पिछला रिकॉर्ड: एंडरसन सिल्वा - लगातार 16 UFC जीत

### अन्य महत्वपूर्ण परिणाम

- सह-मुख्य कार्यक्रम में, मैकेंजी डर्न ने कनाडा की गिलियन रॉबर्टसन को निर्णय से हराकर अपनी UFC महिला स्ट्रॉवेट चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक बचाव किया।

## लेट्स रिवाइज

- ❖ ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? **नई दिल्ली, भारत**
- ❖ 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? **भारत**
- ❖ भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय क्या है? **"लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण"**
- ❖ राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 कौन प्रदान करेगा? **डॉ. जितेंद्र सिंह**
- ❖ कौन सा विभाग राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों का आयोजन करता है? **पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू)।**
- ❖ अनुभव प्लेटफॉर्म का उपयोग कौन कर सकता है? **केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त कर्मचारी, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी।**
- ❖ FAST-DS का फुल फॉर्म क्या है? **छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति-प्रकटीकरण योजना।**
- ❖ FAST-DS 2026 कब लागू हुआ? **16 अगस्त 2026।**
- ❖ ईस्पोर्ट्स विश्व कप 2026 शतरंज का खिताब किसने जीता? **मैग्नस कार्लसन**
- ❖ मैग्नस कार्लसन किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? **नॉर्वे**
- ❖ 2026 EWC शतरंज प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? **पेरिस, फ्रांस**
- ❖ आरबीआई के नए लोन रिकवरी नियम कब लागू होंगे? **1 जनवरी 2027।**
- ❖ गलत डिवाइस प्रतिबंध के लिए कितना मुआवजा देय हो सकता है? **₹250 प्रति घंटा।**
- ❖ रिकवरी एजेंटों के आचरण के लिए कौन जिम्मेदार है? **ऐसा विनियमित ऋणदाता या बैंक जो उन्हें नियुक्त करता हो।**
- ❖ किस नियामक ने ऋण प्रतिभूतियों के लिए क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर का प्रस्ताव रखा? **सेबी**
- ❖ सेबी द्वारा प्रस्तावित क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर के तहत कितनी जोखिम श्रेणियां प्रस्तावित हैं? **छः**
- ❖ किस क्रेडिट-रेटिंग रेंज को क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर में मैप किया जाएगा? **ए से डी**
- ❖ क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर किस मौजूदा तंत्र पर आधारित है? **म्यूचुअल फंड रिस्क-ओ-मीटर**

- ❖ मेजर जनरल सुनील कुमार राजदान कौन थे? भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी और कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता जो सेना के पहले व्हीलचेयर जनरल बने।
- ❖ सुनील राजदान को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला? कीर्ति चक्र।
- ❖ मेजर जनरल सुनील राजदान के सैन्य करियर को किस बात ने ऐतिहासिक बनाया? वह भारतीय सेना के पहले व्हीलचेयर जनरल बने।
- ❖ शांति का क्या अर्थ है? भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और उन्नति।
- ❖ शांति नियम, 2026 का मसौदा किस अधिनियम के तहत तैयार किया जा रहा है? शांति अधिनियम, 2025।
- ❖ किस विभाग ने शांति नियमों का मसौदा जारी किया? परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)।
- ❖ उपकर क्या है? किसी विशिष्ट, निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कर।
- ❖ किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय उपकर और अधिभार को विभाज्य कर पूल से बाहर रखा गया है? अनुच्छेद 270.
- ❖ BOCW सेस क्या है? निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए भूमि लागत को छोड़कर निर्माण लागत पर 1% उपकर।
- ❖ हिमाचल प्रदेश ने पेट्रोल-डीजल पर कितना विधवा और अनाथ उपकर लगाया है? 60 पैसे प्रति लीटर।
- ❖ समिति के विचारार्थ विषयों के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)।
- ❖ विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति से किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)।
- ❖ वित्त तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार के लिए किस प्रणाली की जांच की जा सकती है? TReDS - ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम।
- ❖ UFC 330 मुख्य कार्यक्रम किसने जीता? इस्लाम मखचेव
- ❖ मखचेव ने कौन सी उपाधि बरकरार रखी? UFC वेल्टरवेट चैम्पियनशिप
- ❖ मखचेव ने किसका पिछला रिकॉर्ड पार किया था? एंडरसन सिल्वा, जिन्होंने लगातार 16 UFC जीत हासिल कीं।



# *The* **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

## *Daily* **NEWS CHRONICLE**

### IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

### CONTACT US



+91 8434931877



achievers\_ias\_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA